जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 333 प्रभात चूरू, बुधवार 2 अप्रैल, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर वोट करेगा

### हालांकि संभावना है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने के कारण यह बिल लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो जाएगा

- भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य रुप से मौजूद रहने का आदेश दिया है।
- सत्तारुढ़ एन.डी.ए. के घटक जद (यू) और तेलुगूदेशम पहले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे पर अब वे बिल के पक्ष में वोट करेंगे और उन्होंने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है।
- ज्ञातव्य है कि जद (यू) और तेलुगूदेशम के विरोध पर ही वक्फ विधेयक जेपीसी को भेजा गया था और इन दलों द्वारा प्रस्तावित संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं।
- इंडिया ब्लॉक के भी सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी की है। विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का विरोध करेगा।
- बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार उससे पहले वक्फ बोर्ड बिल पारित करा लेना चाहती है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। ''इंडिया'' गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दल सामूहिक रूप से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ वोट देंगे। यह विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये मंगलवार शाम को इंडिया ब्लॉक के सभी विपक्षी दलों की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि ये सभी दल पूरी चर्चा में भाग लेंगे तथा उसके बाद सभी सामूहिक रूप से विधेयक के विरूद्ध वोट देंगे।

अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में रखा जायेगा। यह तो तय सा है कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जायेगा, क्योंकि तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) तथा जनता दल (यू) इसका समर्थन करेंगे।

पहले इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था तथा जेपीसी की माँग की थी तथा सरकार, अपने मित्र दलों के दबाव पर, जेपीसी के लिये सहमत भी हो गई थी।

टीडीपी तथा जेडी (यू) दोनों ही दलों ने, तीन पंक्ति का व्हिप जारी करके अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने तथा वक्फ विधेयक पर सरकार का समर्थन करने के लिए कहा है।

वक्फ विधेयक को पारित करने में टीडीपी के समर्थन के बदले में, सरकार उसके तीन संशोधनों पर सहमत हो गई है।

विपक्ष ने भी विधेयक का विरोध करने के लिये अपने सदस्यों के लिये व्हिप जारी किये हैं तथा ऐसी आशा की जा रही है कि विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का मुकाबला करेगा तथा मोदी सरकार के हिन्दू -मुस्लिम एजेंडे की बखिया उधेड़ेगा।

बजट सत्र 4 अप्रेल को समाप्त होना है तथा सरकार की कोशिश है कि संसद के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने से पहले, वक्फ विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाये।

## मुख्यमंत्री भजनलाल की राज्य कर्मचारियों को सौगात

- राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश दिए।

जयपुर, 1 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत् (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की सौगात दी है। पैंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि देय होगी। उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्मिकों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद पहले कार्यदिवस पर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना देरी किए राज्य में भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता तथा मंहगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पैंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पैंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'जिनके घर गिराए हैं उन्हें 6 सप्ताह में दस लाख रूपए हर्जाना दिया जाए'

### सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में लोगों के घर गिराए जाने को अमानवीय कृत्य बताते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया

- जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भूयान की बैंच ने प्रयागराज में दादागिरी से मकान तोड़े जाने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश में कानून का राज है और ''आश्रय स्थल का अधिकार'' भी कोई चीज़ है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता, ज़ुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद तथा अन्य लोग, जिनके घर तोड़े हैं, की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने हमारी अन्तर्रात्मा को हिला दिया है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय आज योगी आदित्यनाथ सरकार तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर भारी नाराजगी जताई और शहर में घरों को गिराये जाने को ''अमानवीय और अवैध'' करार दिया।

जस्टिस अभय एस. ओका तथा उज्जल भूयान की बैंच ने मकान तोडने की कार्यवाही को मनमानी और दादागिरी पूर्ण बताते हुए कहा कि ''देश में कानून का शासन'' है और नागरिकों के घर इस तरह नहीं ढहाये जा सकते।

बैंच ने कहा, ''इस घटना ने हमारी अन्तर्रात्मा को झकझोर दिया है। ''आश्रय का अधिकार'' (राइट टु शैल्टर) तथा ''कानून की उचित प्रक्रिया'' जैसी भी कोई चीज होती है।''

इसलिये शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिये कि जिनके भी मकान तोड़े हैं उन मकान मालिकों को वह छः सप्ताह के अन्दर 10 लाख रू. का हर्जाना दें।

शीर्ष अदालत एडवोकेट ज़ुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद तथा अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिनके मकान गिरा दिये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी प्रयागराज में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त झाड़ लगाई थी, तथा कहा था कि इससे ''स्तब्धकारी एवं गलत संकेत'' जाता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने गलतफहमी में मकान ढहा दिये थे, उसने ऐसा लगा कि वह जमीन अपराधी-राजनेता अतीक अहमद की है, जो 2023 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका था।

## तमिलनाडु भाजपा में कौन लेगा अन्नामलाई की जगह?

### तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में तीन नाम सबसे आगे हैं

- पहले नम्बर पर हैं, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, जो पूर्व में भी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं।
- इसके बाद तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर जाति के कद्दावर नेता सांसद एल. मुरुगन का नाम चर्चा में हैं।
- अब यह एकदम साफ है कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई के दिन पूरे हो चुके हैं। असल में अन्नाद्रमुक ने अन्नामलाई को हटाने की शर्त रख दी थी। भाजपा नेतृत्व ने अन्नाद्रमुक नेतृत्व को मनाने की बहुत कोशिश की, पर, पलानीस्वामी टस से मस नहीं हुए।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। तमिलनाडु भाजपा भारी परेशानी में है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी नेतृत्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को बदलने पर विचार कर रहा है। अन्नामलाई के विकल्प के रुप में तीन नाम चर्चा में हैं।

चर्चा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक से गठबंधन की खातिर अन्नामलाई को हटाया जा रहा है। इस पद के लिए तेलंगाना की राज्यपाल और तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन, तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर समुदाय के कद्दावर नेता और सांसद एल. मुरुगन प्रमुख हैं।

असल में अन्नाद्रमुक ने भाजपा के सामने गठबंधन के लिए अन्नामलाई को हटाने की पूर्व शर्त रखी है। अन्नाद्रमुक ने लोकसभा चुनावो से पहले अन्नामलाई के व्यवहार के कारण भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। तब ऐसा लग रहा था मानो भाजपा गठबंधन तोड़ना चाहती थी। और तमिलनाडु में अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है। अन्नामलाई अन्नाद्रमुक के नेताओं खासकर जयललिता के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे। अन्नाद्रमुक के प्रमुख ई. पलानीस्वामी इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया।

भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की पर पलानीस्वामी नहीं माने। अभी भी उनकी यही शर्त थी कि अगर अन्नामलाई रहे तो गठबंधन नहीं होगा। अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता कोवाई सत्यन ने एक निजी टीवी चैनल से वार्ता में बताया कि जहां तक तमिलनाडु में गठबंधन का सवाल है अन्नाद्रमुक का ही पलड़ा भारी रहेगा। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का नेता कौन होगा इसका निर्णय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अन्य राज्यों के दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

- हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के एक मामले में सुनवाई करते हुए इन अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए।

जयपुर, 1 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में प्रदेश से बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार सहित करीब एक दर्जन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। तथापि, उनका यह कहते हुए चयन नहीं किया गया कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश से बाहर का है। इसको चुनौती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पूर्वोत्तर राज्यों को घेरने के लिए चीन को आमंत्रित किया यूनुस ने

- बाँग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य ''लैण्ड लॉक्ड'' अर्थात् भूमि से घिरे हुए हैं, उनके पास समुद्र तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। इसलिए समुद्र के संरक्षक हम हैं।
- यूनुस के इस बयान को लेकर भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों व विभिन्न दलों ने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भारी विरोध जताया।
- असल में पूर्वोत्तर राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक) के जरिए शेष भारत से जुड़े हुए हैं। यह नेपाल व बाँग्लादेश के बीच का संकड़ा मार्ग है। चीन और भूटान इसके काफी समीप हैं, इसलिए भारी चिंता जताई जा रही है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। बाँग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अपनी हाल की टिप्पणियों में, अपने देश को भारत के ''लैण्ड लॉक्ड'' (भूमि से घिरे हुये) पूर्वोत्तर राज्यों के लिये महासागर का ''एकमात्र अभिभावक/संरक्षक'' बताया है। उन्होंने चीन को बाँग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के लिये आमंत्रित किया है। मुहम्मद यूनुस की उक्त टिप्पणी और चीन को दिये गये आमंत्रण का भारत में जबरदस्त विरोध शुरु हो गया है।

अपनी हाल ही चीन यात्रा के दौरान, बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने चीन से उनके देश (बाँग्लादेश) में निवेश करने का अनुरोध किया था तथा कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का लैण्डलॉक्ड होना एक अवसर सिद्ध हो सकता है। यूनुस ने कथित रूप से कहा कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य लैण्डलॉक्ड हैं। उनके पास महासागर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। (इसलिये) महासागर के एकमात्र संरक्षक हम ही हैं। इससे एक बहुत बड़ी संभावना (का द्वार) खुलता है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है।''

यूनुस के इस बयान से भारत में सुरक्षा-संबंधी चिन्ताएं पैदा हो गई हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ''बाँग्लादेश, भारत को घेरने के लिये चीन को आमंत्रित कर रहा है। यह एक खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही है तथा अरुणाचल में चीन ने गाँव बसा ही दिये हैं। हमारी विदेश नीति इतनी करुणाजनक एवं दयनीय है कि जिस देश को अस्तित्व में आने के लिये भारत ने मदद की थी, वही आज हमारे खिलाफ लामबंदी कर रहा है।''

शिव सेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एक ऐसी ''खतरनाक स्थिति'' बताया है, जो भारत की रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य आज सिलगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ''चिकन'स नैक'' भी कहा जाता है, के जरिए शेष भारत से जुड़े हुये हैं। यह नेपाल और बाँग्लादेश के बीच, जमीन की एक सँकरी सी पट्टी है तथा भूटान और चीन इस कॉरिडोर से कुछ सौ किलोमीटर दूर ही हैं।

यूनुस के इस ताजा बयान से उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री बड़े उत्तेजित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने के अन्य ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर से नहीं गुज़रते हों। सरमा ने कहा कि यूनुस का यह बयान भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक कॉरिडोर) से जुड़ी ''स्थायी रूप से असुरक्षित स्थिति (परसिस्टैन्ट वल्नरेबिलिटी नैरेटिव) को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा, ''हमें वैकल्पिक रास्ते तलाशने ही होंगे, भले ही इस कार्य में इंजीनियरिंग-संबंधी जबरदस्त चुनौतियाँ सामने आयें।''

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि यूनुस बाँग्लादेश की भू-राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए पूर्वोत्तर को एक ''रणनीतिक बंधक'' (स्ट्रैटेजिक पॉन) के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूनुस से आग्रह किया कि वे ''अविवेकी बयान'' न दें, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

## नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कहा, अभियुक्त युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है, उस पर नरमी नहीं बरती जा सकती।

जयपुर, 1 अप्रैल। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 जून, 2021 को वह वैवाहिक समारोह में करौली गया हुआ था और उसकी पत्नी काम करने घर से बाहर गई थी। शाम को पत्नी के घर आने पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## दो बाघों को रैस्क्यू कर सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व भेजा

- मध्यप्रदेश में रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से रैस्क्यू किए गए टाइगर्स को लेकर प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं।

रायसेन/भोपाल, 01 अप्रैल। वन विहार भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व की रेस्क्यू टीम, पशु चिकित्सकों एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से दो बाघों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के उपरांत दोनों टाइगर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित ढंग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया।

भोजपुर से लगे हुए वन क्षेत्र बीट भोजपुर में भोजपुर-ईमलिया मार्ग पर एक माह से दो टाइगर्स का लगातार विचरण बना हुआ था। इन टाइगरों ने 5 मवेशियों का शिकार किया था। टाइगर के विचरण के कारण ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। टाइगरों का खेतों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## '27 प्रतिशत मतदाता स्टालिन को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं'

### सी वोटर सर्वे में यह भी खुलासा हुआ कि सुपर स्टार विजय का राजनीति में प्रवेश स्टालिन के लिए परेशानी पैदा कर सकता है

- सी वोटर सर्वे के अनुसार, 27 प्रतिशत वोट के साथ स्टालिन अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों, ई. पलानीस्वामी और अन्नामलाई से काफी आगे है, जिन्हें दस-दस प्रतिशत वोट मिले हैं, पर, विजय 18 प्रतिशत वोट लेकर स्टालिन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
- हालांकि, द्रमुक इस बात से खुश है कि जनता ने द्रमुक व स्टालिन के नेतृत्व में भरोसा जताया है, पर, युवा वर्ग में एक्टर विजय की अपील को अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासकर ''एंटी इन्कम्बैंसी'' फैक्टर को देखते हुए।
- सर्वे में 15 प्रतिशत वोटर्स ने द्रमुक सरकार के काम काज पर पूर्ण संतोष, 36 प्रतिशत ने कुछ हद तक संतोष जताया, पर, 25 प्रतिशत ने असंतोष जाहिर किया और 24 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी। यह 49 प्रतिशत वोटर्स द्रमुक की चिंता का प्रमुख कारण हैं।
- द्रमुक के लिए अभी तक राहत की बात यही है कि विपक्ष बंटा हुआ है। पर, अगर अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन, जिसके गंभीर प्रयास हो रहे हैं, हो जाता है तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। इलैक्टोरल सर्वे और ओपीनियन पोल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से इस समय जो एजेण्डा इन मीडिया कवायदों को प्रेरित कर रहे हैं उसे देखते हुए और तमिलनाडु सरकार के प्रदर्शन और मौजूदा राजनैतिक हालात पर हुए सर्वे को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

लेकिन सी वोटर, जो कि नियमित रुप से जनता की राय को ट्रैक करता रहता है, ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पूर्व करवाए गए अपने सर्वे में पाया है कि आगामी चुनावों में मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन काफी आगे हैं और जनता की राय पूछे जाने पर जनता ने उन्हें पहली पसंद बताया।

मुख्यमंत्री पद के लिए 27 प्रतिशत लोगों ने स्टालिन को प्राथकिता दी वहीं भाजपा के अन्नामलाई और अन्नाद्रमुक के ई. पलानीस्वामी को दस-दस प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया।

सी वोटर सर्वे ने बताया कि एक्टर विजय जो हाल ही में राजनीति में आए हैं, की पार्टी टीवी के शेष विपक्ष से आगे है, उन्हें 18 प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन दिया। एक तरह से यह नवीनतम सर्वे त्रिकोणात्मक संघर्ष का संकेत देता है पर इसमें द्रमुक का पलडा भारी है बशर्ते अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन हो जाए, अन्यथा चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिससे द्रमुक के जीतने की संभावना और बढ़ जाती है।

सर्वे को लेकर द्रमुक की खुशी का सबसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)